मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संग बैठक में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भूमि अधिग्रहण अनिवार्यता 20 फीसदी घटाई

सड़क की मंजूरी 70% जमीन पर ही

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की योजनाओं की स्वीकृति का रास्ता अब आसान होगा। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए 90 फीसदी जमीन के अधिग्रहण की अनिवार्यता को केंद्र सरकार ने घटा कर 70 फीसदी कर दिया है। इस तरह पहले की जरूरत के मुताबिक 20 फीसदी कम अधिग्रहित जमीन पर ही सड़क की स्वीकृति दी जा सकेगी। इससे बिहार की कई पुरानी लंबित परियोजनाओं के साथ ही नई सड़कों के लिए भी राह आसान हो जाएगी।

दिल्ली में बुधवार की रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने इसका आग्रह किया था। केंद्र से मिली इस राहत के बाद तत्काल राज्य की आधा दर्जन सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। इनमें महत्वपूर्ण है 107 राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके तहत महेशखूंट से सहरसा और सहरसा से पूर्णिया तक की सात मीटर चौड़ी सड़क बननी है। इसके लिए 197 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है।

मोकामा पुल के चालू होने का मार्ग भी अब प्रशस्त होगा। जमीन अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों के कारण ही पुल के पहुंच पथ के निर्माण का काम शुरू नहीं हो पा रहा था। अब पहुंच पथ का निर्माण जल्द शुरू हो सकेगा। इसके बाद पुल को चालू कर दिया जाएगा। बैठक में राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भी मौजूद थे।

नई दिल्ली में बुधवार को नितिन गडकरी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

आठ को होगी बैठक

नीतीश कुमार और नितिन गडकरी के बीच हुई बात पर लिए गए निर्णय के आलोक में आठ सितंबर को केंद्र और बिहार सरकार के पदाधिकारियों की दिल्ली में बैठक होगी। इसमें योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। इस बैठक में जेपी सेतु के समानांतर पुल बनाने पर भी चर्चा होगी। यह पुल पटना रिंग रोड का हिस्सा है। इस पर सहमति बन चुकी है।

प्रधानमंत्री पैकेज पर काम में आएगी तेजी

प्रधानमंत्री पैकेज की सड़क योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर भी बैठक में सहमति बनी। जिन सड़कों का टेंडर नहीं हो सका है, उन्हें जल्द किया जाएगा। जिनका टेंडर हो गया है, वहां काम जल्द शुरू कराया जाएगा। गांधी सेतु के समानांतर पुल, सोन नदी पर बनने वाले पंडुका पुल, कोसी नदी पर फुलौत और भेजा के पास पुल, मुंगेर-भागलपुर-मिर्जाचौकी-राष्ट्रीय उच्च पथ की स्थिति आदि योजनाओं पर भी बातें हुई।

विकास की योजनाओं में सहयोग करे केंद्र

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य की विकास योजनाओं में केंद्र सहयोग करे। जनहित कार्यों के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बाद में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण में छोटी-मोटी समस्याएं आती हैं। इसको लेकर कई सड़कों के निर्माण में दिक्कतें आई हैं। इसी को ध्यान में रख कर नितिन गडकरी के साथ विचार-विमर्श हुआ है। दिक्कतों को समाप्त करने के उपाय पर सहमति बनी है।